THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) During 1990 and 1991 Central teams conducted sample surveys in Kerala State which contribute about 98 per cent of total pepper production in the country.

(c) The steps taken to protect pepper cultivators, under the Central Sector Integrated Programme for Development of Spices, are given below :—

(i) Rehabilitation of old pepper gardens which are senile and disease affected;

(ii) Supply of input-kits and subsidised distribution of plant protection sprayers;

(iii) Supply of disease-free planting material;

(iv) Laying out pepper demonstration plots.

Besides, in order to protect pepper growers in Kerala from distress sale, market intervention scheme in pepper is being implemented from 29-4-1993 to 30-6-1993. Under this scheme Central and State Marketing agencies are procuring pepper at Rs. 33 per kg. of fair average quality. The total quantity proposed to be procured is 3000 tonnes.

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का विकास

*267 **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हैक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई है तथा इसे खेती योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ख) क्या यह भूमि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए खेती करने हेतु उनमें वितरित किए जाने की संभावना है; यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) उत्तर प्रदेश में 1989-90 की स्थिति के अनुसार कुल परती भूमि (पुरानी और वर्तमान परतियां) करीब 2.03 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान है। भूमि का विषय जिसमें परती भूमि का विकास/सुधार का काम भी शामिल है, मूलतः राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है और उस पर उसी की (राज्य सरकार की ही) नीतियां और दिशा निर्देश लागू होते हैं। फिर भी, केन्द्र सरकार की उत्पादकता बढ़ाने तथा संबंधित समस्याग्रस्त भूमि को उत्पादनशील उपयोग में लाने योग्य बनाने की दृष्टि से भूमि पर आधारित कुछेक कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अन्य कामों के साथ-साथ परती भूमि के क्षेत्र में कमी करने में भी सहायता मिल रही है।

(ख) खेती के लिए ठीक की गई/विकसित की गई भूमि, भूमिहीनों में वितरित करने/सौंपने का विषय भी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। वैसे, सामान्यतया इसके लिए राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों, भूमिहीन ग्रामीण गरीबों आदि को प्राथमिकता देती है।

उत्तर प्रदेश में विज्ञान शिक्षा सुधार योजना

*268 **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में विज्ञान शिक्षा सुधार योजना के अंतर्गत कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इसकी क्या उपलब्धि रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) से (ग) "स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना में राज्य/संघ शासित प्रदेशों में विशेष कार्यक्रम आरम्भ

करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इस योजना के अधीन, राज्यों संघ शासित प्रदेशों को जब कभी उनसे योजना के मानदंडों के अनुसार तैयार किए गए उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, कुछ अनुमोदित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अतः राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

इस योजना के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 1987-88 से 1990-91 के दौरान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए 7,25,01,840 रु. की धनराशि संस्वीकृत की गई थी :—

—3,359 अपर प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटों का प्रावधान;

—810 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में नई विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना;

—527 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपूर्ण विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन;

—1,337 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए विज्ञान से सम्बद्ध विषयों की पुस्तकों की आपूर्ति;

—विज्ञान शिक्षा के लिए 36 जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना; और

—विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन :—

(क) अपर प्राथमिक स्तर—50

(ख) माध्यमिक स्तर—50

(ग) संसाधन व्यक्ति—8

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1991-92 और 1992-93 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से योजना के मानदण्डों और धनराशि मुक्त करने की कार्यविधि संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

UNESCO Aid for Conservation of Sanchi and Satdhara in M.P.

*269. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that UNESCO propose to provide aid for conservation of Sanchi and Satdhara in M.P.; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Yes Sir.

(b) UNESCO has agreed to assist India in its endeavour to preserve and develop centrally protected monuments at Sanchi and Satdhara in Raisen District of Madhya Pradesh under the Japanese Trust Fund for preservation of World Cultural Heritage. Various activities such as the extensive scientific clearance, conservation and preservation, environmental development of those monuments have been proposed in the 1st phase for the consideration of UNESCO.

KVS in 2000 A.D.

*270. SHRI N. GIRI PRASAD : DR. R. K. PODDAR : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kendriya Vidyalaya Sangathan has received a paper entitled, "KVS in 2000 A.D.";

(b) if so, what are the salient features of the paper; and

(c) what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (c) A paper titled, "A peep into KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN IN 2000 A.D." authorised by Shri H. L. Sonar and dated